RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 073
दि. 15.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


# गुजरात में कैंसर इलाज की मजबूत व्यवस्था, मुख्यमंत्री राहत कोष बना हजारों मरीजों के लिए जीवनदान

**(जीएनएस)**। गुजरात में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष आज एक भरोसेमंद सहारा बनकर उभरा है। खासतौर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में जहां आम परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है, वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष ने हजारों मरीजों और उनके परिजनों को नई उम्मीद दी है। प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और गंभीर रोगों के समय मदद के उद्देश्य से शुरू किया गया यह कोष अब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इसे अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जन-केन्द्रित बनाया गया है, ताकि किसी भी नागरिक को सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े।

सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि लोगों का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे अत्यंत महंगे उपचारों में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और लंबी अवधि के उपचार की जरूरत होती है, जिसकी लागत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री राहत कोष ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इलाज का रास्ता आसान किया है।

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच गुजरात में कैंसर से पीड़ित 2,106 मरीजों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे आर्थिक सहायता दी गई है। इस अवधि में कुल 31.55 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कैंसर मरीजों के उपचार के लिए

वितरित की गई, जिससे हजारों परिवारों को समय पर इलाज मिल सका। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन मरीजों में 450 लोग ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, जबकि 1,656 मरीज अन्य प्रकार के कैंसर से जूझ रहे थे। इन सभी मामलों में राहत कोष की मदद ने मरीजों को नया जीवन देने का काम किया है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए आवेदक की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा छह लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ निवासी प्रमाण-पत्र, अस्पताल द्वारा दिया गया उपचार का विस्तृत खर्च अनुमान और आवश्यक मेडिकल दस्तावेज जमा करना होते हैं। आवेदन मिलने के बाद राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है और इसके बाद पूरी फाइल मुख्यमंत्री राहत कोष समिति के समक्ष रखी जाती है। इस समिति में राहत आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), मुख्य सचिव और स्वयं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। समिति की मंजूरी मिलते ही स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल या मरीज के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि इलाज में किसी तरह की देरी न हो।

गुजरात में कैंसर के बेहतर इलाज के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद का गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजकोट का नथालाल पारिख कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बी.टी. सावानी हॉस्पिटल, सूरत का भारत कैंसर हॉस्पिटल, किरण मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और AAIHMS जैसे संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए समय पर उपचार सुनिश्चित होता है।

राज्य सरकार का मानना है कि इलाज केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज और उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक संबल देना भी उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री राहत कोष इसी सोच का परिणाम है, जिसने हजारों जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में संभाला है। कैंसर जैसे गंभीर रोग में जहां हर दिन कीमती होता है, वहां यह कोष इलाज में देरी की सबसे बड़ी बाधा, यानी आर्थिक परेशानी, को दूर करने में सफल रहा है। आज गुजरात में मुख्यमंत्री राहत कोष केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भरोसे, संवेदनशीलता और जीवनरक्षा का प्रतीक बन चुका है।

## एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 'रहमान डकैत' पर कसा तंज, महायुति को महापौर चुनाव में जीत की भविष्यवाणी

**(जीएनएस)**। नागपुर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम सप्ताह में विपक्ष और विशेष रूप से उबाठा गुट पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि मुंबई की तिजोरी पर डाका डालने वाला 'रहमान डकैत' आखिर कौन है। शिंदे ने भरोसा जताया कि आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में महायुति ही असली 'धुरंधर' साबित होगी और जनता ऐसे तत्वों को करारा जवाब देगी।

अधिवेशन के दौरान शिंदे ने कहा कि सरकार लगातार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को गति दे रही है, जबकि विपक्ष केवल निराधार आरोप लगाने तक सीमित रह गया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ विपक्षी नेता नागपुर सिर्फ "पर्यटन" के लिए आते हैं – आज आते हैं, कल चले जाते हैं – न सवाल पूछते हैं, न जनता के मुद्दों पर कोई ठोस विचार रखते हैं। उपमुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष लंबे समय तक केवल पद की राजनीति में लगा रहा, जनसमर्थन की कमी के बावजूद, और उपमुख्यमंत्री पद खत्म करने की मांग करना उनकी हताशा और सुविधाजनक

भूल को दर्शाता है।

मुंबई के लिए सरकार द्वारा किए गए बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि ओसी रहित 20 हजार इमारतों को राहत दी गई, पगड़ी-मुक्त मुंबई की दिशा में कदम उठाए गए, 13 हजार इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता खोला गया, नेशनल पार्क क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवास सुनिश्चित किया गया, मिल जमीन पुनर्विकास नियमों में सुधार किया गया और सिडको घरों की कीमतों में 10% की कटौती की गई। साथ ही, बड़े भूखंडों पर क्लस्टर पुनर्विकास को बढ़ावा दिया गया। शिंदे ने कहा कि बाळासाहेब ठाकरे के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे 40 लाख झोपड़पट्टीवासियों को बेहतर घर मिलेंगे।

एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि मुंबई को वर्षों तक सत्ता में रहने वाले कुछ लोग केवल लूट का माध्यम मानते रहे और ऐसे 'रहमान डकैत' को जनता अब पहचान चुकी है। उन्होंने यह दोहराया कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव में महायुति ही विजेता बनेगी और जनता के भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरेगी। उनका कहना था कि विकास कार्यों, जनकल्याण और शहरी सुधारों के लिए महायुति सरकार प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप और भ्रम फैलाने में लगा हुआ है।

उपमुख्यमंत्री का यह बयान आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक रणनीति और महायुति की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता के विश्वास और विकास के एजेंडे के बल पर महायुति आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी और शहर की राजनीति में स्थायित्व और सुधार की नई दिशा निर्धारित होगी।

## टेक्नोलॉजी से न्याय प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाने की दिशा में CJI सूर्यकांत का जोर, कहा– तकनीक विकल्प नहीं, साधन बने

**(जीएनएस)**। कटक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था में तकनीक के महत्व और सीमाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य न्यायिक निर्णय को पूरी तरह प्रतिस्थापित करना नहीं होना चाहिए। उनका स्पष्ट संदेश था कि तकनीक केवल न्यायाधीशों और अदालतों की सहायता का माध्यम हो, जबकि अंतिम फैसला हमेशा मानवीय विवेक और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली का हर सुधार और तकनीकी नवाचार तभी सफल होगा, जब वह आम नागरिकों, विशेषकर गरीब, बुजुर्ग और तकनीक से अपरिचित लोगों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित कर सके।

CJI सूर्यकांत यह संबोधन ओडिशा के कटक में आयोजित संगोष्ठी 'आम आदमी के लिए न्याय सुनिश्चित करना: मुकदमेबाजी की लागत और देरी को कम करने की रणनीतियां' में दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबित मामले और महंगे मुकदमे आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक लंबित मामलों

के बढ़ते बोझ पर चिंता जताई और इसे पूरे ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था में देरी केवल कानूनी दिक्कत नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष असर डालने वाली समस्या है।

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त अदालतें और संसाधन उपलब्ध कराए बिना कोई भी न्यायिक प्रणाली दबाव में कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों का बोझ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा न्याय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और लोगों का भरोसा घटता है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई के अनुभव का भी उल्लेख किया और बताया कि उस कठिन समय में तकनीक ने न्याय की पहुँच बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

CJI ने डिजिटल दुरुपयोग के खतरों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों, डीपफेक और ऑनलाइन सिस्टम के गलत इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी और जोर दिया कि डिजिटल सुधार अगर गरीबों, बुजुर्गों और तकनीक से अपरिचित लोगों को पीछे छोड़ देता है, तो वह सुधार नहीं बल्कि प्रतिगमन है। उनका कहना था कि तकनीक को न्यायिक निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि न्याय को बाधित करने के लिए।

सूर्यकांत ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि तीनों स्तंभों के सामंजस्य के बिना कानून का शासन संतुलित नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर सुनवाई और निर्णय सुनिश्चित करना न्याय की मूल भावना है, चाहे कानूनी प्रावधान बनें या प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय का लक्ष्य केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में असरदार और समयबद्ध परिणाम देना भी होना चाहिए।

सीजेआई सूर्यकांत ने निष्कर्ष रूप में यह कहा कि तकनीक न्याय का विकल्प नहीं, बल्कि न्याय को सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाने का साधन होना चाहिए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को आम नागरिक के हित को प्राथमिकता देने, नवाचारों को संतुलित तरीके से लागू करने और न्यायिक प्रणाली को हर वर्ग के लिए समान रूप से प्रभावी बनाने का मार्गदर्शन दिया। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय न्यायिक प्रणाली को आने वाले समय में और अधिक समावेशी, भरोसेमंद और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।

## सूडान में यूएन इमारत पर ड्रोन हमला: 6 बांग्लादेशी पीसकीपर्स की मौत, गंभीर संकट जारी

**(जीएनएस)**। सूडान। सूडान के दक्षिणी कोर्डोफान प्रांत की राजधानी कादुगली में रविवार को संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक इमारत पर ड्रोन हमले ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय प्रयासों को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 6 संयुक्त राष्ट्र पीसकीपर्स की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतक और घायल पीसकीपर्स बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। यह हमला UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei) के कैंप पर हुआ, जो लंबे समय से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का केंद्र रहा है।

यूएनआईएसएफए ने पुष्टि की कि छह सैनिक मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि घायलों में से चार की हालत नाजुक है। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है, और राहत व बचाव कार्य युद्धग्रस्त इलाके की जटिल परिस्थितियों के बीच जारी है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध बताया। उन्होंने कहा कि पीसकीपर्स को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता और हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बांग्लादेश सरकार ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए अपने नागरिक पीसकीपर्स को तत्काल और पर्याप्त सुरक्षा तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की संयुक्त राष्ट्र से अपील की। ढाका स्थित विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और आवश्यक कदम उठा रही है।

प्रारंभिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कादुगली स्थित UN बेस पर ड्रोन हमले में आग और भारी धुआं उठता दिखाई दिया। सूडानी सेना ने सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो साझा किया, जिसमें बेस को हुए नुकसान के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। स्थानीय प्रशासन ने पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) को हमले का जिम्मेदार ठहराया, हालांकि RSF ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनका इस हमले या UN मुख्यालय से कोई संबंध नहीं है।

कादुगली क्षेत्र लंबे समय से गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। पिछले डेढ़ साल से यह इलाका घेराबंदी और सैन्य संघर्ष के अधीन है। नवंबर की शुरुआत में यहां अकाल की घोषणा हुई थी, और अप्रैल 2023 से जारी गृहयुद्ध में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि हजारों की जान जा चुकी है। हाल ही में दक्षिणी कोर्डोफान के कालोगी इलाके में हुए हमलों में एक किंडरगार्टन और अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें 114 लोग मारे गए, जिनमें 63 बच्चे भी शामिल थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन हमले से सूडान में पहले से ही गंभीर सुरक्षा और मानवीय स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। स्थानीय प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय राहत संगठन संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सैन्य टकराव और भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच पीड़ितों तक समय पर राहत पहुंचाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इस हमले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेताया है कि सूडान में शांति स्थापना और पीसकीपिंग मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

## अक्षरधाम में राष्ट्रीय सम्मेलन: हिंदू ग्रंथों में प्रार्थनाओं के दार्शनिक, साहित्यिक और भक्ति आयामों पर गहन मंथन

**(जीएनएस)**। दिल्ली। स्वामिनारायण अक्षरधाम स्थित बीएपीएस स्वामिनारायण शोध संस्थान ने रविवार को "हिंदू ग्रंथों में प्रार्थनाएं: दार्शनिक, साहित्यिक और भक्ति आयाम" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देशभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से विद्वान, शोधार्थी और छात्र उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य सनातन ग्रंथों में प्रार्थना की अवधारणा को समग्र दृष्टिकोण से समझना और इसके दार्शनिक, साहित्यिक तथा भक्ति आधारित पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करना था।

सम्मेलन का शुभारंभ संस्थान के सहायक निदेशक डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी ने किया। उन्होंने प्रार्थना की दार्शनिक प्रासंगिकता और समकालीन संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संस्थान के अध्यक्ष महामहोपाध्याय भद्रेशदास स्वामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि प्रार्थना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, मानसिक संतुलन और मोक्ष प्राप्ति का भी प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों और शोधार्थियों से अपील की कि वे प्रार्थना की बहुआयामी महत्ता को समझें और इसके अध्ययन को और गहन बनाएं।

सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों और भक्ति साहित्य पर आधारित अपने मौलिक शोध प्रस्तुत किए। इन शोधों में वेदों की स्तुति परंपरा, भक्ति साहित्य में शरणागति और अनन्य प्रेमभाव, प्रार्थना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इसके सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। शोध प्रस्तुतकर्ताओं में डॉ. नरेंद्रकुमार पंड्या (प्राचार्य, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय), शालिनी सारस्वत और डॉ. माध्वी प्रमुख रूप से शामिल रहीं।

सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं के रूप में प्रो. मुरली मनोहर पाठक (कुलपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय), प्रो. शिव शंकर मिश्रा (कुलपति, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन), प्रो. डी. बालगणपति (दिल्ली विश्वविद्यालय), प्रो. उपेंद्र राव (जेएनयू), प्रो. ओमनाथ बिमली (दिल्ली विश्वविद्यालय) और प्रो. गिरिशचंद्र पंत (जामिया मिलिया इस्लामिया) उपस्थित रहे। उन्होंने अपने व्याख्यानों में प्रार्थना के दार्शनिक, साहित्यिक और भक्ति पक्षों को जोड़ते हुए बताया कि किस प्रकार प्रार्थना केवल व्यक्ति के आंतरिक अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज और संस्कृति के विकास में भी इसका महत्व है। समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हिमानी मेहता ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन के दौरान यह निष्कर्ष सामने आया कि हिंदू परंपरा में प्रार्थना का अध्ययन न केवल आध्यात्मिक अनुभवों को गहरा करता है, बल्कि इसके माध्यम से समाज में नैतिकता, शांति और एकता को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्वानों ने इस दिशा में आगे शोध और चर्चा को जारी रखने का संकल्प लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रार्थना की गहन समझ और उसका समग्र महत्व संपूर्ण रूप से समझाया जा सके।


नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus

DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

## संपादकीय

# अवसर और चुनौती

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता की रीढ़ है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में एसआईआर की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने का फैसला भले सरल प्रशासनिक निर्णय प्रतीत हो, पर इसके प्रभाव बहुत व्यापक और बहुस्तरीय हैं। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य जितना आवश्यक है, उतना ही कठिन भी और इसीलिए यह समय वृद्धि महत्वपूर्ण अवसर के साथ चुनौती भी है।

यह तो बहुत स्पष्ट है कि यदि इसका उपयोग पूरी गंभीरता से हो तो इस अतिरिक्त समय का मतदाता सूची की शुद्धता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश के सभी जिलों से मिली रिपोर्टें संकेत देती हैं कि फील्ड सत्यापन में कई क्षेत्रों में देरी थी, कुछ स्थानों पर अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान अपूर्ण थी और मृतक मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी धीमी चल रही थी। दो सप्ताह का अतिरिक्त समय इन खामियों को दूर करने का अवसर देगा और इससे सूची की शुद्धता में उल्लेखनीय सुधार आ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले जिलों, शहरी स्लम क्षेत्रों, प्रवासी मज़दूरों के अंचलों और बाढ़-सूखा प्रभावित इलाकों में, जहां सत्यापन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस समयवृद्धि से एसआईआर में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक सवाल यह भी है कि क्या इतनी विशाल जनसंख्या वाले सूबे में अधिकारी और समय की मांग कर सकते हैं? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हर विधानसभा क्षेत्र में 8–10 प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित हैं। ये वो लोग हैं जो या तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, या स्थानांतरित हो चुके हैं, या पता बदल चुके हैं।

यदि इनका सत्यापन अधूरा रह गया, तो स्थिति चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी मतदान की आशंका को बढ़ा सकती है, क्योंकि फर्जी वोटिंग और मृत मतदाताओं के नाम से मतदान की आशंकाएं अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान कि विपक्ष मृत या अनुपस्थित नामों पर वोट अपने खाते में डलवा सकता है, राजनीतिक चेतावनी भी है और प्रशासनिक सावधानी भी। सिद्धांततः यह संभव तो है, पर तभी जब सूची में कमियां रह जाएं। तकनीकी निगरानी और आधार-लिंकिंग के बावजूद, यदि फील्ड स्तर पर ढील हुई तो यह खामी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अतः यह बयान अधिकारियों पर यह दबाव भी डालता है कि कोई चूक न रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जिलों में अधिकारियों को फील्ड में जाकर गायब, विस्थापित और अनुपस्थित मतदाताओं की खोज का आदेश दिया है। घुसपैठियों को मतदाता सूची से दूर रखने के लिए 'डोर-टू-डोर सत्यापन, डिजिटल फॉर्मों की ट्रैकिंग, आधार-मतदाता फोटो क्रॉस-मैचिंग, और संदिग्ध इलाकों की विशेष जांच करवानी आवश्यक होगी। कुल मिलाकर इस बढ़े समय का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब प्रशासनिक मशीनरी में जवाबदेही बढ़े, तकनीकी तथा फील्ड- दोनों स्तरों पर सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मतदाता सूची चुनाव की नींव है। नींव मजबूत होगी तो लोकतंत्र भी ताकतवर होगा।

# दिल्ली का 'पुतिन' महोत्सव... वे आए और चले गए!

> "रूस भारत के साथ मित्रता चाहता है, चीन को उलझाए रखने के लिए लेकिन क्या चीन को 'लाल आंख' दिखाने की हिम्मत भारतीय हुक्मरानों में है, खरा सवाल यह है। प्रधानमंत्री मोदी के भक्त उन्हें विश्वगुरु और अन्य उपाधियों से सुशोभित करते हैं।

रशियन राष्ट्रपति पुतिन का ४ तारीख को दिल्ली में आगमन हुआ। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गले लगाया और अगले दो दिन वे पुतिन उत्सव में तल्लीन रहे। पुतिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्लीभर की सड़कें बंद कर दी गईं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए दिल्ली में पहले से ही जाम लगे रहते हैं। जब ये दोनों नेता बाहर निकलते हैं तो आधे घंटे पहले ही यातायात रोक दिया जाता है। इससे लोगों को असुविधा होती है। शाह कृष्णा मेनन रोड पर रहते हैं। इस सड़क और इसके तीनों तरफ की सड़कें यातायात के लिए बंद होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में पुतिन के आने से समस्या और बढ़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले राष्ट्रपति ट्रंप की आरती उतारी। अब ये सभी लोग 'पुतिन' की आरती उतारते नजर आए। यह तस्वीर मजेदार थी। पुतिन ६ तारीख को लौट गए। राष्ट्रपति भवन में उनके लिए भोज का आयोजन किया गया। भोज के दो दिन बाद दिल्ली के अखबारों में एक तस्वीर छपी। तस्वीर में टेंट ठेकेदार लाल गलीचे लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर आ रहे हैं। पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली में तंबूवालों से कालीन किराए पर लिए गए थे। पहली बात तो यह है कि पुतिन के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद कालीन पर्याप्त नहीं थे। दूसरी बात, पुतिन जैसे विदेशी मेहमान जब आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उनके स्वागत के लिए पर्याप्त कालीन नहीं होते। पूरा दृश्य और पृष्ठभूमि सजाई जाती है। पुतिन को पता ही नहीं कि उनकी पीठ पीछे क्या हुआ और न तो राष्ट्रपति ट्रंप और न ही पुतिन भारत के संकट के समय मजबूती से खड़े रहे हैं। हर एक को भारत में अपना सामान बेचना है। राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी रक्षा सामग्री भारत के माथे फेंकनी है और पुतिन को अपना तेल बेचना है। पिछले दस

वर्षों में भारत की कमर टूट चुकी है इसलिए जो भी आएगा वह भारत का शोषण करेगा। रूस कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था। उन्होंने इसे कई बार अपने कार्यों से साबित किया है और मैंने स्वयं मॉस्को में यह अनुभव किया है कि रूस में पीढ़ियां भले ही बदल गई हों, लेकिन नेहरू-गांधी और राज कपूर के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ है। रूस के कई टुकड़े हो गए। भले ही वह पहले जैसा बलशाली रूस नहीं रहा हो, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि वैश्विक स्तर पर रूस की भूमिका अमेरिका और चीन के बाद एक 'महाशक्ति' की है। रूस चीन के पक्ष में खड़ा है या भारत के यह अभी तक रहस्य बना हुआ जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। रूस भारत के साथ मित्रता चाहता है, चीन को उलझाए रखने के लिए लेकिन क्या चीन को 'लाल आंख' दिखाने की हिम्मत भारतीय हुक्मरानों में है, खरा सवाल यह है। प्रधानमंत्री मोदी के भक्त उन्हें विश्वगुरु और अन्य उपाधियों से सुशोभित करते हैं। ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारतीय रुपया हर दिन गिर रहा है और डॉलर के मुकाबले ९० के पार पहुंच गया है। यह दुखद है। जिस देश की मुद्रा इस तरह गिर रही हो, वह देश दुनिया में गरदन उठाकर कैसे खड़ा हो सकता है?

जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आए, तब भारत की समग्र तस्वीर क्या थी? भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डे पर अराजकता का माहौल था। हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लाखों यात्री चार दिनों तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे। सभी समाचार पत्रों में पुतिन-मोदी के गले मिलने की तस्वीरों के साथ-साथ भारत में हवाई क्षेत्र में मची अफरा-तफरी की तस्वीरें भी प्रकाशित हुरइं। पुतिन को इस भारत के दर्शन हुए। पुतिन ने मोदी की प्रशंसा की, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पुतिन बाड़ पर थे और आज पुतिन को भारत से ज्यादा चीन पसंद है। चीन खुलेआम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वह लड़ाकू विमान, हथियार और गोला-बारूद मुहैया करा रहा है। पुतिन और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हैं इसलिए मोदी-पुतिन के गले मिलने का कोई अर्थ नहीं है। पुतिन की भारत यात्रा के बाद गौतम अडानी को रूस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। बाबा रामदेव की 'पतंजलि' इंडस्ट्री ने दिल्ली में मॉस्को सरकार के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत पतंजलि को मॉस्को में कुशल श्रमिक (Skilled Labour) और स्वास्थ्य सेवाएं (Wellness Services) मुहैया कराने का ठेका मिला है। पुतिन की यात्रा के दौरान भाजपा समर्थित व्यापार मंडल ने अपना काम साध लिया है। बाबा रामदेव के स्वास्थ्य उत्पाद अक्सर 'नकली' साबित होते रहे हैं। उनका घी भी मिलावटी निकला, लेकिन अब वह रूस को भारत में न चल पाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराकर व्यापार करेंगे। सरकार ने पुतिन के सम्मान में एक शाही भोज का आयोजन किया। संसद के दोनों ही विपक्षी दल नेताओं को भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। राहुल गांधी संसद परिसर में खड़े होकर बोले, 'विदेशी मेहमानों को विपक्षी नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र विरोधी है।' मानो पुतिन मोदी-शाह के साले हैं और मोदी-शाह ने पुतिन को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यह कुछ ऐसे हो रहा था जैसे वहां पर किसे आमंत्रित किया जाना चाहिए, ये उनका अपना मामला है।

जब विदेशी मेहमान आते हैं तो वे देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से मिलते हैं। यह लोकतंत्र के लिए सम्मान की बात है, लेकिन मोदी के आने के बाद से यह परंपरा बंद हो गई है। हमारे विपक्षी नेता उच्च शिक्षित हैं। उन्हें विश्व राजनीति का अच्छा ज्ञान है। प्रधानमंत्री मोदी को शायद डर रहा होगा कि वे विदेशी मेहमानों पर उनसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया यह माहौल पसंद आया होगा कि भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन हम विपक्षी दल को महत्व नहीं देते। उनके देश में लोकतंत्र की स्थिति भारत से अलग नहीं है। रूस में संसद से लेकर सभी संस्थाएं पुतिन के नियंत्रण में हैं। पुतिन एकतरफा चुनाव जीतते हैं। पुतिन के खिलाफ आवाज उठानेवालों को गायब कर दिया जाता है। आज रूस में विपक्षी दल का अस्तित्व न के बराबर है। पहले पुतिन के मनमाने शासन के खिलाफ लड़नेवाले प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जब वे बच गए तो उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर साइबेरिया की जेल में कैद किया गया और वहीं कैद में उनकी हत्या कर दी गई। यह रूस का लोकतंत्र है और विपक्ष के दलों की हालत।

इसलिए पुतिन को दिल्ली पसंद आई और उन्होंने मोदी से यह सवाल भी नहीं पूछा होगा कि क्या आपके देश में कोई विपक्षी दल है। २००४ से २०१४ तक, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं ने १६२ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में कई प्रतिनिधिमंडलों को विदेश और संयुक्त राष्ट्र भेजा। पुतिन से लेकर ओबामा तक, कई विश्व नेता २०१४ से पहले दिल्ली आए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये औपचारिक दौरे थे, लेकिन मोदी सरकार ने लोकतंत्र की सभी परंपराओं को तोड़ दिया। उन्होंने विश्व नेताओं के सामने यह छवि पेश की कि हमने अपने देश में विपक्ष को खत्म कर दिया है। पुतिन आए, उन्होंने भारत के हवाई अड्डों पर अराजकता देखी। विपक्ष की आवाज उन तक जरूर पहुंची होगी। उसी समय, भारतीय संसद में विपक्ष द्वारा 'वंदे मातरम' को लेकर सत्तारूढ़ दल की जमकर आलोचना की जा रही थी!

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दल का गला घोंटकर खुद को ही घुटन में डाल दिया!

## प्रेरणा

# स्मृति, प्रकृति और चेतावनी की गहरी कथा बनता काव्य-संग्रह 'एक नदी का न होना'

प्रकृति प्रेमी कवि रमेश पठानिया का हाल ही में प्रकाशित कविता-संग्रह 'एक नदी का न होना' किसी एक विषय पर लिखी गई कविताओं का साधारण संकलन नहीं है, बल्कि यह एक लंबी, निरंतर और गहन कथा की तरह सामने आता है, जिसमें स्मृति, प्रकृति और वर्तमान समय की चेतावनी एक-दूसरे में घुलती चली जाती हैं। इस संग्रह का मूल स्वर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू उपत्यका में बहने वाली व्यास नदी है, लेकिन यह स्वर धीरे-धीरे केवल एक नदी की चिंता से आगे बढ़कर मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की व्यापक पड़ताल बन जाता है। कवि जिस 'न होने' की बात करता है, वह अचानक समाप्त हो जाने का नहीं, बल्कि धीरे-धीरे घटते अस्तित्व, सिकुड़ते बहाव और मौन होती प्रकृति की पीड़ा का संकेत है, जिसे वह शब्दों में दर्ज करता है।

रमेश पठानिया की कविताओं में प्रकृति हमेशा एक जीवंत उपस्थिति रही है। पेड़, पहाड़, हवा, रास्ते और बचपन की स्मृतियां उनकी कविता में बार-बार लौटती रही हैं, लेकिन इस संग्रह में यह उपस्थिति और भी गहन हो जाती है। व्यास नदी यहां केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह एक सजीव पात्र की तरह कवि के साथ चलती है, बोलती है और चुप होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। कवि नदी को देखकर केवल वर्तमान को नहीं देखता, बल्कि उसमें अतीत की छवियां भी पढ़ता है, वे दिन जब नदी अपने पूरे विस्तार में बहती थी, जब उसके किनारे जीवन की चहल-पहल थी और जब उसका अस्तित्व किसी खतरे की तरह महसूस नहीं होता था। आज वही नदी कवि को असहज करती है, क्योंकि उसमें उसे भविष्य की एक खाली और भयावह तस्वीर दिखाई देती है।

संग्रह में विकास के नाम पर हो रहे अतिक्रमण की पीड़ा भी स्पष्ट रूप से उभरती है। कवि यह महसूस करता है कि जिस विकास को मनुष्य अपनी उपलब्धि मानता है, वही विकास नदियों के लिए विनाश का कारण बनता जा रहा है। बांध, सड़कें, सुरंगें और निर्माण कार्य नदियों के स्वाभाविक प्रवाह को रोक रहे हैं और उन्हें उनके ही किनारों से बेदखल कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानव जीवन भी इसकी कीमत चुकाने लगता है। 2023 में बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में कवि का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। उसे लगता है कि यह आपदाएं अचानक नहीं आतीं, बल्कि लंबे समय से की जा रही उपेक्षा और छेड़छाड़ का परिणाम होती हैं।

रमेश पठानिया नदियों और स्त्रियों के बीच जो समानता स्थापित करते हैं, वह इस संग्रह को और भी धारदार बना देती है। वे मानते हैं कि दोनों को ही सहनशील समझकर उन पर अत्याचार किया गया है। दोनों को झेलने वाला, सब कुछ देने वाला और कभी शिकायत न करने वाला मान लिया गया है। लेकिन कवि चेतावनी देता है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जिस तरह स्त्री अत्याचार का प्रतिकार करती है, उसी तरह नदी भी एक दिन अपना उत्तर देती है, और वह उत्तर विनाश के रूप में सामने आता है। यह विचार संग्रह में किसी नारे की तरह नहीं, बल्कि अनुभव और पीड़ा के स्तर पर उतरता है।

नदी के न होने की कल्पना कवि को भीतर तक हिला देती है। वह सोचता है कि यदि व्यास नदी न रहे, तो कुल्लू की घाटी कैसी होगी, वह दृश्य कैसा होगा जिसे निकोलस रोरिक जैसे कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स में अमर किया है। वह उन घाटियों, किनारों और पहाड़ों को पल भर के लिए बिना नदी के देखता है और स्वयं को शून्य से भरा हुआ पाता है। यह शून्य केवल दृश्य का नहीं है, बल्कि स्मृति और पहचान का शून्य है। नदी के साथ जुड़े अनुभव, कहानियां, गीत और जीवन की लय सब एक साथ खो जाने की आशंका कवि को बेचैन कर देती है।

इसी बेचैनी से उपजकर कवि पाठक से आग्रह करता है कि वह नदी को देखे, लेकिन यह देखना साधारण देखने जैसा नहीं है। यह देखने का अर्थ है रुककर, ठहरकर और जिम्मेदारी के साथ महसूस करना। कवि चाहता है कि नदी को केवल संसाधन, पर्यटन स्थल या बिजली उत्पादन का साधन न समझा जाए, बल्कि उसे एक जीवित सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसके साथ मनुष्य का रिश्ता साझेदारी का है, स्वामित्व का नहीं। इसी भावना से कवि यह इच्छा भी प्रकट करता है कि व्यास नदी को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिले, ताकि उसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल स्थानीय लोगों या कुछ संवेदनशील व्यक्तियों तक सीमित न रहे। इस तरह 'एक नदी का न होना' धीरे-धीरे एक व्यक्तिगत काव्य अनुभव से आगे बढ़कर सामूहिक चेतना का दस्तावेज बन जाता है। यह संग्रह पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि नदियां नहीं बचीं, तो केवल जल ही नहीं सूखेगा, बल्कि हमारी स्मृतियां, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान भी संकट में पड़ जाएगी। रमेश पठानिया की कविताएं भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ती हैं कि क्या हम समय रहते उस नदी को बचा पाएंगे, जिसका न होना हमारे होने को भी अधूरा कर देगा।

# अराजकता का कूपन

अब इंडिगो ने अपनी अराजकता पर पर्दा डालने के मद्देनजर 'कूपन' (वाउचर) बांटने की पेशकश की है। ये कूपन 10,000 रुपए के होंगे और 'गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों' को ही दिए जाएंगे। क्या ऐसे यात्रियों की परिभाषा और पात्रता इंडिगो ने स्पष्ट की है? क्या सरकारी तंत्र भी 9 लाख से अधिक यात्रियों की परेशानी और नुकसान की कीमत की भरपाई इस कूपन को स्वीकार कर रहा है? क्या अदालत इस कूपन को मान्यता देगी? फिलहाल मौखिक बयान आ रहे हैं कि ये कूपन मुआवजे से अतिरिक्त होंगे। यात्री अगले 12 माह तक इंडिगो की किसी भी यात्रा में इन कूपन का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन इंडिगो ने डीजीसीए के नियमानुसार अभी तक मुआवजा नीति को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया है। यह अनिवार्य नियम है। सरकारी निर्देश ये भी हैं कि मुआवजा नकद, बैंक ट्रांसफर अथवा यात्री की सहमति पर ही कूपन के रूप में दिया जा सकता है। एकतरफा कूपन की पेशकश नियमानुसार नहीं है। बहरहाल देश ने टीवी चैनलों पर एक चित्र देखा होगा, जिसमें इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़े केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू के पास बैठे हैं, मानो देश से माफी मांग रहे हों! देश ऐसे माफ नहीं करेगा। इंडिगो ने उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती का शैड्यूल सरकारी तंत्र के सामने रखा है, लेकिन गुरुवार, 11 दिसंबर, को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की 220 उड़ानें भी कंपनी ने रद्द की हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह पूर्वघोषित था? नतीजा यह रहा कि यात्रियों को एक बार फिर तकलीफ, परेशानी उठानी पड़ी। इंडिगो की कार्य-प्रणाली और गवर्नेंस मॉडल की जांच सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी शुरू कर दी है। इंडिगो का संचालन मॉडल ही संदेह के घेरे में माना जा रहा है। सेबी का बयान आया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को नोटिस जैसी संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। इंडिगो को डीजीसीए ने ही दो गंभीर नोटिस जारी कर रखे हैं। चार सदस्यीय समिति ने भी कंपनी के सीईओ से सवाल-जवाब किए हैं। इंडिगो के मुख्यालय में डीजीसीए की निगरानी टीम तैनात कर दी गई है, जिसमें तकनीकी अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो कोई जुर्माना थोपा है और न ही कोई अन्य दंड दिया है, बल्कि गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से संसद को बताया गया कि इंडिगो ने 2024-25 में कुल 7253 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि अन्य विमानन कंपनियां घाटे में रहीं। सरकार को इस पहलू की भी चिंता करनी पड़ेगी कि विमानन कंपनियां घाटे में क्यों हैं?

क्या इंडिगो उनकी उड़ानों पर कब्जा करके मुनाफा कमा रही है? यही कारण हो सकता है कि इंडिगो का विमानन क्षेत्र में एकाधिकार है। क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती? जब इंडिगो के कारण देश के लाखों यात्री बंधक की स्थिति में थे, तो दूसरी कंपनियों ने खूब कालाबाजारी की। यह सवाल दिल्ली उच्च न्यायालय में भी उठा कि विमानन कंपनियों ने सरकार द्वारा किराया तय करने, फ्रीज करने के बावजूद 80-90 हजार रुपए तक का किराया कैसे वसूल किया? उच्च न्यायालय का निर्देश है कि लूट की यह रकम यात्रियों को वापस की जाए। भारत कोई 'केला गणतंत्र' देश नहीं है कि मनमर्जी के किराए वसूले जाएंगे और इंडिगो जैसी कंपनियां सरकार के आदेशों को मानने से इंकार कर देंगी। इंडिगो ने यह नहीं बताया है कि कितनी देरी, मिस्ड कनेक्शन अथवा रात भर फंसे यात्रियों को स्वतः ही कूपन का पात्र मान लिया जाएगा। एक अनुमान बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं, लिहाजा करीब 5 लाख यात्रियों को 'गंभीर रूप से प्रभावित' मानना चाहिए। यह तो इंडिगो स्पष्ट करेगी। बहरहाल यह आर्थिक अराजकता भी है और सार्वजनिक सेवा में एकाधिकार का दुरुपयोग भी है, लिहाजा सभी विमानन कंपनियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह दायित्व भारत सरकार का ही है। सवाल यह है कि जब नए नियम सभी एयरलाइन कंपनियों पर लागू होते हैं, पर इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो पर ही क्यों दिखा? इसका जवाब है कि इंडिगो के पास पायलटों की कमी हो गई है। इंडिगो ने जानबूझ कर यह कमी की। अन्य एयरलाइंस कंपनियों की तरह इंडिगो के पास भी नए पायलटों की भर्ती के लिए पर्याप्त समय था, किन्तु कंपनी ने भारी आर्थिक भार को टालने के लिए भर्ती नहीं की।

## अभियान

# स्वप्न में क्यों आते हैं मृत स्वजन, आस्था, मनोविज्ञान और संस्कृति के पन्नों में छिपे हैं इसके गहरे अर्थ

अक्सर लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वे नींद में अपने उन स्वजनों को देख लेते हैं जो इस संसार से विदा हो चुके होते हैं। कोई माता-पिता को देखता है, कोई दादा-दादी को, तो कोई किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति को जो जीवन में अत्यंत निकट रहा हो। स्वप्न टूटते ही मन में एक अजीब-सी हलचल मच जाती है, कभी सुखद अनुभूति होती है तो कभी मन भारी हो जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसे स्वप्नों को केवल कल्पना या संयोग नहीं माना गया है, बल्कि इनके पीछे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर गहरे कारण बताए गए हैं। संस्कृति के पन्नों में झांकने पर यह स्पष्ट होता है कि मृत स्वजनों का स्वप्न में आना मानव मन और आत्मा की एक सूक्ष्म प्रक्रिया का संकेत है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई आत्मीय व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसका रिश्ता केवल देह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्मृति, संस्कार और भावनाओं के रूप में वह हमारे भीतर जीवित रहता है। स्वप्न अवस्था में जब चेतन मन शांत होता है और अवचेतन सक्रिय होता है, तब वही दबे हुए भाव, अधूरी बातें और अनकहे रिश्ते चित्र बनकर सामने आते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि कभी-

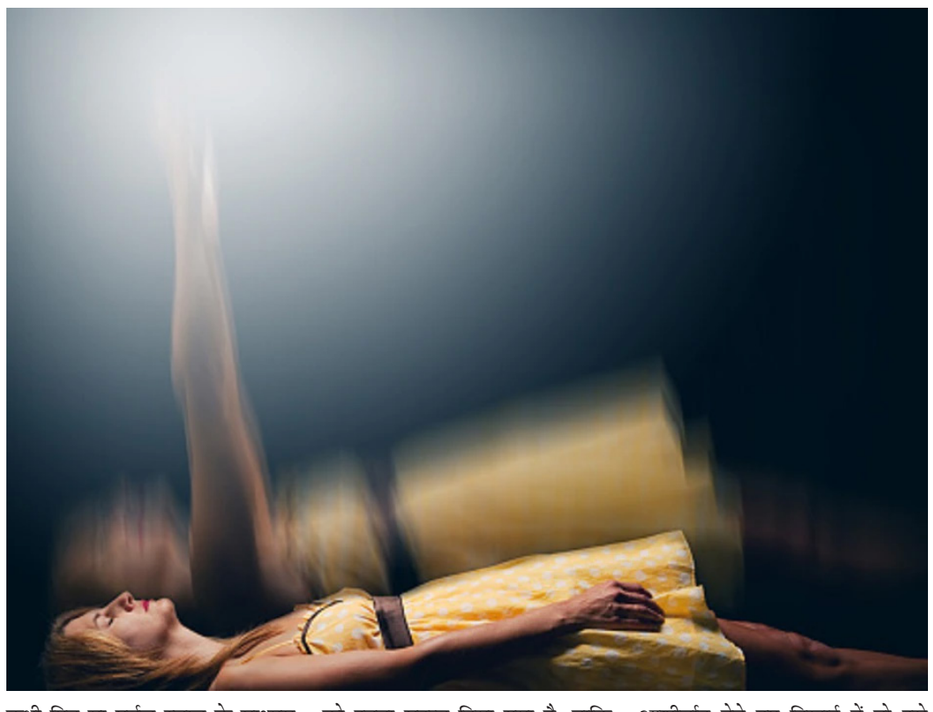

कभी पितृ या पूर्वज स्वप्न के माध्यम से संकेत देते हैं, विशेषकर तब जब वे किसी बात से प्रसन्न हों या किसी कारण से असंतुष्ट हों। यही कारण है कि भारत में पितृ पक्ष, श्राद्ध और तर्पण को इतना महत्व दिया गया है, ताकि जीवित और दिवंगत के बीच का यह सूक्ष्म संबंध संतुलन में बना रहे।

संस्कृति यह भी कहती है कि यदि मृत स्वजन स्वप्न में शांत, प्रसन्न या आशीर्वाद देते हुए दिखाई दें तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा स्वप्न जीवन में किसी अच्छे परिवर्तन, संकट से मुक्ति या सही मार्ग पर बढ़ने का संकेत हो सकता है। वहीं यदि वही स्वजन दुखी, मौन या कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो इसे आत्ममंथन का अवसर माना जाता है। ऐसे स्वप्न व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, आचरण और परिवारिक मूल्यों की ओर लौटने का संदेश देते हैं। कई बार यह भी माना जाता है कि ऐसे स्वप्न पितृदोष, अधूरे संस्कार या परिवार में चल रही किसी असंतुलित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मृत स्वजनों का स्वप्न में आना शोक, स्मृति और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा होता है। जिन लोगों से हमारा गहरा लगाव रहा हो, उनका जाना मन के भीतर एक रिक्त स्थान छोड़ देता है। समय के साथ हम ऊपर से सामान्य दिखने लगते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वह शून्य बना रहता है। स्वप्न उसी शून्य की भाषा होते हैं। जब मन किसी दबाव, तनाव या भावनात्मक उलझन में होता है, तब वही प्रिय चेहरे स्वप्न में आकर सांत्वना भी देते हैं और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

भारतीय संस्कृति में स्वप्न को केवल मानसिक गतिविधि नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा माना गया है। उपनिषदों और पुराणों में कहा गया है कि स्वप्न अवस्था वह सेतु है जहां जाग्रत और सूक्ष्म लोक के बीच संवाद संभव होता है। इसलिए मृत स्वजनों का स्वप्न में दिखना कभी-कभी केवल स्मृति नहीं, बल्कि संस्कारों का जागरण भी होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किन मूल्यों से आए हैं, किस परंपरा के वाहक हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है।

इसी कारण संस्कृति के पन्ने यह सिखाते हैं कि ऐसे स्वप्न आने पर डरने या अत्यधिक व्याकुल होने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने जीवन, व्यवहार और रिश्तों को देखना चाहिए, पितरों का स्मरण कर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और यदि मन कहे तो दान, सेवा या किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि वह सूक्ष्म संबंध भी संतुलित हो जाता है, जो जीवित और दिवंगत के बीच आज भी बना हुआ है।

अंततः स्वप्न में मृत स्वजनों का दिखना जीवन और मृत्यु के बीच उस अदृश्य पुल की याद दिलाता है, जहां रिश्ते देह से आगे बढ़कर भावना और चेतना का रूप ले लेते हैं। संस्कृति हमें सिखाती है कि ऐसे स्वप्न भय का नहीं, बल्कि समझ, स्मृति और संस्कार का विषय हैं, जो हमें अपने भीतर और अपने अतीत से जोड़ते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

# “संवेदनशील सरकार, सुरक्षित नागरिक”: गुजरात CMRF ने 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को दिया नया जीवनदान

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) संकट की घड़ी में राज्य के नागरिकों के लिए एक सशक्त सुरक्षा-कवच के रूप में उभरा है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से लेकर गंभीर बीमारियों और जीवन-रक्षक उपचारों तक, इस कोष का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र में CMRF ने हजारों परिवारों को समय पर मदद, आर्थिक राहत और नई उम्मीद प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री राहत कोष को अधिक संवेदनशील, त्वरित और जन-केन्द्रित बनाया गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहे। उनकी प्राथमिकता “लोगों का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि” के अनुरूप यह कोष आज आम नागरिकों के लिए वास्तविक सहारा और भरोसे का माध्यम बन चुका है।

### गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन रहा CMRF

गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे मरीजों को जीवन-रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना है, जिनके लिए महंगे उपचार संभव नहीं हो पाते। कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लिवर फेल्योर, तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर स्थितियाँ इस सहायता के दायरे में आती हैं। पात्रता मानदंडों के तहत आवेदक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। इसके साथ निवासी प्रमाण-पत्र, उपचार का विस्तृत अनुमान और संबंधित मेडिकल दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात पूरी फाइल मुख्यमंत्री राहत कोष समिति के समक्ष भेजी जाती है, जिसमें राहत आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), मुख्य सचिव और स्वयं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। समिति की मंजूरी के बाद स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल या रोगी के खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे मरीज को समय पर उपचार में कोई बाधा न आए।

- बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित ब्लड कैंसर के 450 मामलों और अन्य 1,656 कैंसर मरीजों का सहारा बना CMRF
- 2021-2025 के दौरान 2,106 कैंसर रोगियों को उपचार के लिए मिली 31.55 करोड़ से अधिक की मदद
- लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और जटिल उपचारों में भी मिलती है CMRF से वित्तीय मदद

### CMRF से 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को उपचार के लिए मिली 31.55 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता

2021 से 2025 के बीच मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) ने गुजरात में कैंसर से जूझ रहे 2,106 मरीजों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है जिससे उन्हें नया जीवनदान मिला है। इस अवधि में 2,106 कैंसर मरीजों के उपचार के लिए CMRF की ओर से 31.55 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए रोग-वार आंकड़ों के अनुसार, ब्लड कैंसर (जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मामले भी शामिल हैं) के 450 मरीजों को राहत मिली, जबकि अन्य प्रकार के कैंसर से पीड़ित 1,656 मरीजों को CMRF से आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर सहायता के अलावा CMRF के तहत लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और जटिल उपचारों में भी महत्वपूर्ण आर्थिक मदद दी जा रही है।

### गुजरात के शीर्ष कैंसर अस्पतालों में उपलब्ध है CMRF से सीधी आर्थिक मदद

अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GCRI), राजकोट के नथालाल पारिख कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बी.टी. सावानी हॉस्पिटल, सूरत के भारत कैंसर हॉस्पिटल, किरण मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तथा AAIHMS जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत सहायता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी अस्पतालों में कैंसर से संबंधित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में समय पर उपचार भी सुनिश्चित जाता है।

# केरल की राजनीति में नया अध्याय, तिरुवनंतपुरम जीत के बाद भाजपा के विस्तार का भरोसा: मोहन यादव

**(जीएनएस)**। इंदौर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐतिहासिक जीत को दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भाजपा केरल में लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। रविवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव का परिणाम केवल एक स्थानीय जीत नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव का संकेत है, जो केरल की राजनीति में धीरे-धीरे आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसका प्रभाव अब देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विजय पताका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लहरा रही है और जहां-जहां पार्टी को जनता का समर्थन मिला है, वहां सुशासन, विकास और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित हुए हैं। यादव ने यह भी कहा कि केरल जैसे राज्य में, जहां दशकों से वामपंथी दलों का प्रभुत्व रहा है, वहां भाजपा नीत राजग की यह जीत जनता की बदलती सोच और विकास के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे 45 वर्षों से चले आ रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के शासन का अंत हुआ है। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल परंपरा के नाम पर सत्ता नहीं चाहती, बल्कि विकास, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है।

मोहन यादव ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भाजपा केरल में अपनी संगठनात्मक मजबूती बढ़ाएगी और जनता के मुद्दों के साथ लगातार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और सुशासन की नीति का प्रभाव अब केरल की जनता तक भी पहुंच रहा है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में पहले भाजपा को सीमित समर्थन मिलता था, वहां भी अब पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा, विकास और विश्वास के लिए है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में मिली जीत इसी सोच की जीत है। उन्होंने भरोसा जताया कि केरल की जनता आने वाले समय में भाजपा को और अधिक अवसर देगी और राज्य की राजनीति में संतुलन और विकास की नई धारा स्थापित होगी।

# एसआईआर को लेकर बयानबाजी पर मौलाना बरेलवी का कड़ा ऐतराज, अखिलेश यादव से संयम बरतने की अपील

**(जीएनएस)**। बरेली। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, न कि किसी विशेष समुदाय, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाना। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर भ्रामक और गैर-जिम्मेदार बयान देना न केवल गलत है, बल्कि समाज में अनावश्यक भ्रम और तनाव भी पैदा करता है।

मौलाना बरेलवी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मृत मतदाताओं के नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों की प्रविष्टियां और मतदाता सूची में दर्ज तकनीकी त्रुटियों को ठीक किया जाता है। यह एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनाया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों के वोट काटे जाने का आरोप पूरी तरह निराधार और गुमराह करने वाला है। इस तरह के बयान चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, जो उचित नहीं है।

मौलाना रजवी ने कहा कि देश के जिम्मेदार नेताओं को चाहिए कि वे हर मुद्दे को सांप्रदायिक नजरिये से देखने से बचें। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता सभी नागरिकों के हित में होती है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देशभर में मुसलमानों ने एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय, सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए, फॉर्म भरे और चुनाव आयोग के अधिकारियों को सहयोग दिया, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और भरोसेमंद बन सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी यह साबित करती है कि मुसलमान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं और देश की संस्थाओं को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव सहित सभी राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वे तथ्यों के आधार पर बयान दें, अफवाहों से बचें और जनता को भ्रमित करने वाले आरोप लगाने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनावी प्रक्रियाओं को संदेह और राजनीति से ऊपर रखा जाए, ताकि आम नागरिक का भरोसा बना रहे।

# घने कोहरे की चादर में लिपटा नोएडा, सड़कों पर थमी रफ्तार और बढ़ी चिंता

**(जीएनएस)**। नोएडा। औद्योगिक नगरी नोएडा रविवार सुबह घने कोहरे की गिरफ्त में नजर आई, जहां तड़के से ही आसमान से लेकर सड़कों तक सफेद धुंध की मोटी परत छा गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह करीब दस बजे तक शहर के अधिकांश हिस्सों में दृश्यता बेहद कम बनी रही और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए सफर करना पड़ा। खुले और मैदानी इलाकों में दृश्यता घटकर 15 मीटर से भी कम रह गई, जिससे एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चलना जोखिम भरा हो गया।

कोहरे के साथ-साथ वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति ने भी हालात को और बिगाड़ दिया। नोएडा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-91 और एनएच-24 समेत प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सामने से आ रहे वाहनों का पता बेहद नजदीक आने पर चला, जिससे अचानक ब्रेक लगाने और टकराव की स्थिति बनती रही। ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही और कुछ स्थानों पर जाम जैसे हालात भी देखने को मिले।

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 61 प्रतिशत रहने के कारण ठंड के साथ कोहरा और अधिक घना हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि

कम तापमान, नमी और प्रदूषण के मेल ने कोहरे को लंबे समय तक टिकाए रखा, जिससे सुबह के समय हालात सामान्य होने में देरी हुई।

घने कोहरे और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सोमवार से प्रमुख एक्सप्रेसवे और सड़कों पर वाहनों की गति सीमा घटाने का फैसला लागू कर दिया गया है। 15 दिसंबर की रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह व्यवस्था 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसी तरह नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एलिवेटेड रोड पर भी हल्के वाहनों के लिए 50 और भारी वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की सीमा लागू की गई है। यातायात पुलिस ने सड़कों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. प्रवीन रंजन सिंह के अनुसार एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के कारण दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों समेत कुछ श्रेणी के भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके तहत चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज और अशोक नगर जैसे प्रमुख बॉर्डर प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और प्रतिबंधित वाहनों को वहीं से वापस लौटाया जा रहा है। दूर-दराज के राज्यों से दिल्ली की ओर जा रहे कई वाहन चालकों को इस कारण असुविधा का सामना करना पड़ा, हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें नियमों की जानकारी देकर समझाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

# डांस की मस्ती में मौत को दावत, बंदूक लहराकर युवक ने की फायरिंग, VIDEO वायरल होते ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई

**(जीएनएस)**। राजस्थान के डीग जिले से सामने आया एक वीडियो एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जश्न और कानून को चुनौती देने की यह प्रवृत्ति कब थमेगी। नगर थाना क्षेत्र के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा यह वीडियो महज 13 सेकेंड का है, लेकिन इसमें दिखी लापरवाही और बेखौफ रवैया बेहद खतरनाक है। वीडियो में एक लंबे बालों वाला युवक, जिसका नाम जीशान बताया जा रहा है, हाथ में बंदूक लेकर सड़क पर खुलेआम नाचता नजर आता है। डांस के दौरान वह कभी बंदूक को हवा में लहराता है, तो कभी लोगों के बीच घुमाता है और फिर अचानक फायर कर देता है। यह पूरा दृश्य किसी शादी या निजी आयोजन का बताया जा रहा है, जहां आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा की परवाह किए बिना युवक ने यह दुस्साहस किया।

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हलचल मच गई। नगर थाने के एसएचओ लाखन सिंह ने देर रात ही कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से हथियार को भी जब्त कर लिया है और दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है और जिस बंदूक से फायर किया गया वह लाइसेंसी है या अवैध। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब देश के अलग-अलग हिस्सों से हर्ष फायरिंग की वजह से मौत और गंभीर चोटों की खबरें लगातार आ रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी की गोली लगने से मौत हो गई थी। चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में अजयनगर से आई एक बारात के दौरान चली गोली ने पूरे समारोह को मातम में बदल दिया। इसी तरह 25 नवंबर को मेरठ में भी एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में छत से बारात देख रही एक किशोरी की जान चली गई थी। गली में निकली बारात के बीच चली गोली सीधे किशोरी को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इन घटनाओं के बावजूद हर्ष फायरिंग की प्रवृत्ति थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार चेतावनी देती है, अभियान चलाती है और कार्रवाई भी करती है, लेकिन जश्न के नाम पर कानून को ताक पर रखने वाले लोग दूसरों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। डीग का यह मामला भी उसी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना सोच का उदाहरण है, जहां कुछ सेकेंड के दिखावे और शौक के लिए किसी की जिंदगी खतरे में डाल दी गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लग पाती है या नहीं।

# विदेशी पूंजी की लगातार विदाई से बाजार पर दबाव दिसंबर में करीब 18 हजार करोड़ की निकासी

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेचैनी लगातार बनी हुई है और दिसंबर के पहले पखवाड़े में भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जमकर बिकवाली की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार एक से 12 दिसंबर के बीच एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार से लगभग 17,955 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में अब तक विदेशी निवेशकों द्वारा निकाली गई कुल राशि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो बाजार के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि यह बिकवाली कोई एक महीने की घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से विदेशी निवेशकों का रुझान कमजोर बना हुआ है। नवंबर महीने में भी एफपीआई ने करीब 3,765 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी। हालांकि अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने कुछ राहत देते हुए 14,610 करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच लगातार बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। दिसंबर में फिर से तेज निकासी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी निवेशक फिलहाल

भारतीय बाजार को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की इस सतर्कता के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण एक साथ काम कर रहे हैं। रुपये में लगातार कमजोरी, अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंची ब्याज दरें, वैश्विक स्तर पर सख्त मौद्रिक नीति और तरलता की कमी ने उभरते बाजारों से पूंजी निकालने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय शेयरों का मूल्यांकन भी कई विदेशी निवेशकों को महंगा नजर आ रहा है, जिससे वे नए निवेश के बजाय मुनाफावसूली को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के रिसर्च हेड हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाले विकसित बाजारों की ओर झुक रहे हैं। वहीं एंजेल वन के सीनियर एनालिस्ट वकारजावेद खान का कहना है कि साल के अंत में पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये की गिरावट ने भी एफपीआई की बिकवाली को और तेज किया है। इन सभी कारणों का संयुक्त असर भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने के रूप में दिखाई दे रहा है।

इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है, जिसका श्रेय घरेलू निवेशकों को जाता है। दिसंबर के पहले दो हफ्तों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 39,965 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर काफी हद तक संतुलित हो गया। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और अन्य घरेलू संस्थानों की मजबूत भागीदारी ने बाजार को सहारा दिया है और निवेशकों के भरोसे को बनाए रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि वैश्विक हालात में कुछ स्थिरता आती है और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता कम होती है, तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इक्विटी के अलावा डेट बाजार में भी एफपीआई की गतिविधियां मिश्रित रहीं, जहां सामान्य सीमा के तहत 310 करोड़ रुपये की निकासी देखी गई, जबकि वॉलंटरी रिटेंशन रूट के माध्यम से 151 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। कुल मिलाकर विदेशी पूंजी का रुख फिलहाल सतर्क बना हुआ है, लेकिन घरेलू निवेशकों की मजबूती ने बाजार को संतुलन में बनाए रखा है।

# डिजिटल बैंकिंग की नई उड़ान: YONO के जरिए 20 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की तैयारी में SBI

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक नई और निर्णायक छलांग लगाने की तैयारी में है। बैंक ने अपने प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो (YONO) को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए अगले दो वर्षों में इसके यूजर बेस को दोगुना कर 20 करोड़ तक पहुंचाने की योजना बनाई है। एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने स्पष्ट किया है कि बैंक का भविष्य डिजिटल विस्तार से जुड़ा है और योनो 2.0 इस रणनीति की रीढ़ साबित होगा। वर्तमान में योनो से करीब 10 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 20 करोड़ करने के लिए बैंक तकनीकी ढांचे, ग्राहक अनुभव और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है।

चेयरमैन शेट्टी के अनुसार, योनो 2.0 के तहत इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक साझा कोड सिस्टम अपनाया गया है, जिससे सभी डिजिटल चैनलों पर ग्राहकों को एक समान, सुरक्षित और सहज अनुभव मिल सके। इस एकीकृत व्यवस्था से खाता खोलने, लेन-देन, लोन, निवेश और अन्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पहले से कहीं अधिक तेज और सरल होगी। उन्होंने कहा कि योनो केवल एक ऐप नहीं, बल्कि एसबीआई की डिजिटल सोच का केंद्र है, जिसके जरिए बैंक नए उत्पादों और सेवाओं को तेजी से बाजार में उतार सकेगा और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढाल पाएगा। एसबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल विस्तार के बावजूद बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। फिलहाल बैंक को इक्विटी कैपिटल जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगले पांच से छह वर्षों तक लगभग 15 प्रतिशत का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखने की स्थिति में है। चालू वित्त वर्ष में बैंक को करीब 14 प्रतिशत की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बैंकिंग सेक्टर में भरोसे को दर्शाती है।

ऋण वृद्धि के मोर्चे पर एसबीआई का फोकस रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई यानी RAM सेक्टर पर बना हुआ है। यह सेक्टर बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा है और सितंबर तक इसका आकार 25 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर चुका है। इसके साथ ही गोल्ड लोन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि एक्सप्रेस क्रेडिट जैसे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में भी दो अंकों की वृद्धि की संभावना जताई गई है। बैंक का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से इन सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण और ग्राहक पहुंच और अधिक प्रभावी होगी।

एसबीआई प्रबंधन का कहना है कि योनो के माध्यम से बैंक न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग की पहुंच बढ़ाना चाहता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, लेन-देन को सुरक्षित बनाना और ग्राहकों को एक ही मंच पर सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। योनो के जरिए एसबीआई डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत आधार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म देश की बैंकिंग प्रणाली में एक नया मानक स्थापित कर सकता है।

# देश से नक्सलवाद समाप्त करने का डेडलाइन तय, अमित शाह ने बस्तर में दिया विकास और शांति का संदेश

**(जीएनएस)।** जगदलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक-2025 के समापन समारोह में देशभर के लिए नक्सलवाद समाप्त करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और यह लक्ष्य अब वास्तविकता के बेहद करीब है। अमित शाह ने इस अवसर पर माओवादियों से आग्रह किया कि वे हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होता, न तो हथियार उठाने वालों का, न आदिवासियों का और न ही सुरक्षाकर्मियों का। केवल शांति और विकास ही क्षेत्र और देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

अमित शाह ने कहा कि बस्तर में अब डर की जगह उम्मीद ने ले ली है। जहां कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं और पूर्व में दूर का सपना लगने वाले विकास कार्य, जैसे सड़कें, रेलवे और राजमार्ग, अब पूरे क्षेत्र में बन रहे हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में दो हजार से अधिक नक्सलियों

ने हथियार छोड़ दिए हैं। इन युवाओं ने न केवल अपने जीवन को नया आयाम दिया, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने पुनर्वास और विकास योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि जिन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं और जो नक्सलवाद के दौरान घायल हुए हैं, उनके लिए विशेष पुनर्वास योजनाएं लागू की गई हैं। उनका कहना था कि यह सिर्फ़ हथियारबंद कैडरों के खिलाफ कार्रवाई का समय नहीं, बल्कि उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने और क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित करने का समय है। उन्होंने आदिवासी समाज और स्थानीय नेताओं की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने युवाओं को हथियार छोड़ने और समाज में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। अमित शाह ने बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और खेल प्रतिभाओं को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण कर चुके 700 नक्सली खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर देश के लिए एक मिसाल कायम कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध परंपरागत संस्कृति, खानपान, कला, वाद्य और नृत्य का संरक्षण करने की पहल की बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्थापित कर यहां के पारंपरिक गीतों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नक्सलवाद अब बस्तर और पूरे देश में समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने समाज के सभी तबकों से अपील की कि जो भी युवा अभी हथियार लिए हुए हैं, वे पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर विकसित बस्तर और नए भारत की यात्रा में शामिल हों। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2026 में बस्तर ओलंपिक में वे स्वयं लौटकर देखेंगे कि पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है और क्षेत्र विकास, शांति और सांस्कृतिक समृद्धि की मिसाल बन चुका होगा।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाल आतंक के स्थान पर अब "भारत माता की जय" के नारे गूंज रहे हैं, और यह बदलाव न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और भारत के लिए विकास और आशा का संदेश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की नई शुरुआत होगी, जिससे यह देश का एक विकसित और सुरक्षित क्षेत्र बन सकेगा। अमित शाह की यह घोषणा और अपील बस्तर क्षेत्र के युवाओं, आदिवासियों और समाज के सभी वर्गों के लिए न केवल चेतावनी बल्कि प्रेरणा भी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि नक्सलवाद के खात्मे और क्षेत्र के विकास का संकल्प सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका क्रियान्वयन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

## कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली पर अनिल विज और बीजेपी नेताओं का तीखा हमला, सियासत में गरमाई बहस

**(जीएनएस)।** नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा बुलंद किया। रैली का मकसद बीजेपी और चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी के आरोप लगाना था, लेकिन इस पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला किया। विज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी हार और असफलताओं को छुपाने के लिए आरोपों का सहारा लेती रही है और अब यह 'वोट चोरी की तेरहवीं' मना रही है।

मंत्री विज ने कहा कि देश में चुनावों में कांग्रेस लगातार हारती आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय हमेशा EVM पर सवाल उठाती रही है और अब वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। विज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेता अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि वोट चोरी कैसे हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाता सूचियों पर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, वही सूचियां कांग्रेस के पास भी थीं। अगर ये सूचियां गलत थीं तो कांग्रेस

को पहले अपने विधायकों से इस्तीफा लेना चाहिए था, उसके बाद दिल्ली में रैली आयोजित करनी चाहिए थी।

इस बीच पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। जाखड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस, जो इतने सालों तक EVM हैक होने का दावा करती रही, अब कथित वोट चोरी के विरोध में रैली कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर EVM हैक हैं तो फिर किसी को वोट चोरी करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। जाखड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस को पहले तय करना चाहिए कि EVM हैक हैं या वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता भी पार्टी के वोट चोरी के दावों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें लगता है कि जनता के प्रति पार्टी की नीतियों में कमी और नेतृत्व पर घटता भरोसा ही असली कारण हैं, जिसके चलते पार्टी लगातार चुनावों में हार रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस की यह रैली न केवल हार की निराशा और गुस्से का इज़हार थी, बल्कि पार्टी का यह प्रयास था कि आगामी चुनावों में अपना जनाधार मजबूत किया जाए। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा रैली पर किए गए हमलों ने इस राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। विश्लेषकों के अनुसार, आगामी चुनावों में मतदाता और उनकी भावनाएं ही दोनों पार्टियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होंगी। सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो रही है कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के आरोप और बीजेपी की उनकी खामियों पर तीखी टिप्पणियां आगामी चुनावी रणनीतियों का हिस्सा हैं। चुनावी माहौल अब पहले से ज्यादा गर्म और चुनौतीपूर्ण बन गया है, और दोनों बड़े दलों के नेताओं के बयान इस बहस को और अधिक व्यापक और तीव्र बना रहे हैं। जनता की नजरें अब अगले चुनाव और इन आरोप-प्रत्यारोपों पर टिकी हुई हैं।

## जम्मू-कश्मीर: डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने अनंतनाग में की सुरक्षा और अपराध समीक्षा, अधिकारियों को सतर्क रहने का दिया निर्देश

**(जीएनएस)।** अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने शनिवार को अनंतनाग पुलिस स्टेशन में एक व्यापक अपराध और सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में जिले में अपराध, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मौजूदा हालात का विश्लेषण किया गया। डीआईजी मट्टू ने अधिकारियों को सतर्क रहने, सक्रिय पुलिसिंग बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान डीआईजी ने खुफिया नेटवर्क को और सशक्त बनाने, फील्ड इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उभरती चुनौतियों का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार, साइबर अपराध और

अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा, कानून का पालन और समाज में विश्वास कायम करने वाले उपायों को भी प्राथमिकता दी जाए।

डीआईजी मट्टू ने अनंतनाग पुलिस की तत्परता और समर्पण की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों को जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रत्येक अधिकारी व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के साथ काम करे और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए।

इस समीक्षा बैठक में अनंतनाग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह-आईपीएस, एसपी मुख्यालय अनंतनाग कार्तिक श्रोत्रिया-आईपीएस, एसपी ऑपरेशंस फुरकान कादिर, एसपी नॉर्थ ऐशमुकाम रमीज राजा, डीआईजी एसकेआर के एसओ और सीपीओ, डीएसपी अनंतनाग, तथा जिले के सभी एसडीपीओ और एसएचओ शामिल हुए। बैठक में अधिकारी वर्ग ने जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और डीआईजी मट्टू के दिशा-निर्देशों के अनुरूप फील्ड में कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जिले में सुरक्षा उपायों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इस बैठक के बाद अनंतनाग पुलिस ने अपने कर्मियों को अलर्ट मोड में रखा और जिला प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

## दिल्ली के मानसरोवर पार्क में दिनदहाड़े महिला की हत्या मंदिर परिसर में चाकू से हमला; आरोपी सीसीटीवी में कैद

**(जीएनएस)।** दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र में रविवार को दिनदहाड़े एक महिला की हत्या की वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी। जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में दो युवक घुसकर पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी घटना से पहले पुजारी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन पुजारी उस समय परिसर में मौजूद नहीं थे। दोनों आरोपियों ने महिला पर कई बार चाकू से वार किए। वहीं, मौके पर मौजूद एक अन्य महिला ने पीड़िता को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उस पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया।

पुलिस को दोपहर करीब 12 बजे पीसीआर कॉल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ दो महिलाओं को मंदिर परिसर में पाया। दोनों को तुरंत गुरुतेग बहादुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुसुम शर्मा, महेश शर्मा की पत्नी और एमएस पार्क निवासी, की मौत हो गई। हमले में घायल अन्य महिला का इलाज जारी है। घटना डीडीए पार्क स्थित डीडीए फ्लैट्स के भीतर बने मंदिर में हुई।

मंदिर परिसर से निकलते समय आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फुटेज में आरोपी मंदिर की ओर आते समय अपने हाथ में सफेद रंग की पन्नी लिए दिखाई दे रहे हैं। घटना को अंजाम देने के बाद वे खाली हाथ पैदल जाते हुए कैमरे में कैद हुए। मृतका कुसुम शर्मा के पति महेश शर्मा ने बताया कि पूरा विवाद मंदिर की जमीन और रुपए के लेनदेन को लेकर था। उनके अनुसार, कसाना परिवार ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके परिवार से अपनी लड़की की शादी के लिए रुपए उधार लिए थे, जिन्हें लगातार मांगने पर भी वापस नहीं किया गया। पैसे वापस नहीं करने के बजाय कसाना परिवार लगातार जान से मारने की धमकी देता रहा। पिछले तीन साल से इस संबंध में मानसरोवर पार्क थाने में कई शिकायतें दी गईं, और डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेश शर्मा ने बताया कि हमलावर उनका जीवन लेने के लिए आए थे, लेकिन जब वे वहां नहीं थे तो उनकी पत्नी को निशाना बनाया गया। पुलिस ने इस गंभीर घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अंचल सक्सेना को हिरासत में ले लिया है। विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, ऐसे मामले न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं बल्कि स्थानीय समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। पुलिस ने आसपास के इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर परिसरों में सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात की पृष्ठभूमि और विवादित जमीन के मामलों की जांच जारी है, जबकि परिवार और स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।

## पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कल होगी प्रकाशित, जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने नाम की स्थिति

**(जीएनएस)।** पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप में SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई और इन राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ी संख्या में SIR फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है। जिन मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई है, उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे और उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई के दौरान मान्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र आदि की जांच की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही मतदाता का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आयोग ने बताया कि सोमवार को

पश्चिम बंगाल सहित चार प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

मतदाता अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से देख सकते हैं। ऑनलाइन नाम जांचने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर डालना होगा। इसके अलावा, ड्राफ्ट लिस्ट संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगी। वहीं, जो लोग ऑफलाइन जांच करना चाहते हैं, उनके लिए हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध होगी। यदि मतदाता BLO तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ब्रांच लेवल एजेंट (BLA) मदद करेंगे। चुनाव आयोग उन मतदाताओं की सूची भी प्रकाशित करेगा जिनके नाम वोटर रोल से हटाए जाएंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीएलओ ने सभी मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म वितरित किए और उन्हें संग्रहित कर वेबसाइट पर अपलोड किया। प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाने के बावजूद, 11 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में कुल 58,17,851 फॉर्म जमा नहीं हो पाए। यह कुल मतदाताओं का 7.59 प्रतिशत है। इनमें से लगभग 24 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 12 लाख का पता नहीं चल रहा है, लगभग 20 लाख स्थायी रूप से अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं, 1.37 लाख पहले से एनरोल हैं और 57,696 अन्य कारणों से फॉर्म अधूरा या अमान्य रहे हैं। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके लिए प्रक्रिया स्पष्ट है। 16 दिसंबर को संबंधित बूथों पर उनके नाम पब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या मृत/डुप्लीकेट एंट्री से संबंधित दावा या शिकायत कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में एक माह का समय दिया है। सभी दावों की जांच के बाद मतदाता का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन करने और त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक है। मतदाता अपना नाम जांचकर सुनिश्चित करें कि उनका अधिकार सुरक्षित है। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने अधिकार का उपयोग करें और किसी भी समस्या के लिए संबंधित BLO या चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।

## हिमाचल में पाकिस्तानी झंडे वाला संदिग्ध गुब्बारा गिरा, स्थानीय लोगों में दहशत

**(जीएनएस)।** हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शनिवार को एक बार फिर संदिग्ध पाकिस्तानी प्रतीकों वाला गुब्बारा एक मकान की छत पर गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दौलतपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के चालेट गांव की बताई जा रही है, जहां सुबह स्थानीय निवासी पप्पू नंबरदार के परिवार ने अपने घर की छत पर यह बैलून देखा। गुब्बारे को देखकर पूरे गांव में चिंता और आशंका का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रविपाल अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बैलून को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया और आसपास क्षेत्र को घेरकर विस्तृत जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि बैलून में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा या कोई संदिग्ध सामग्री नहीं लगी हुई थी। गुब्बारा आकार में हवाई जहाज जैसा था और उस पर पाकिस्तानी झंडे के निशान स्पष्ट रूप से बने हुए थे। इसके साथ ही बैलून पर "PIA" यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। बैलून पर विदेशी प्रतीकों की उपस्थिति ने स्थानीय लोगों में डर

और आशंका पैदा कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

यह घटना ऊना जिले में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट उपमंडल के तातेहरा गांव में भी तीन संदिग्ध गुब्बारे पाए गए थे। उन गुब्बारों पर "I Love Pakistan" लिखा हुआ था और उन पर भी पाकिस्तानी झंडे के निशान बने हुए थे। उस मामले में भी पुलिस ने सभी गुब्बारों को जब्त कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि तातेहरा गांव में पकड़े गए गुब्बारों को पहले ही जब्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में भी यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये गुब्बारे कहां से आए और क्या इनके पीछे किसी तरह की साजिश तो नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील जारी रखी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे गुब्बारे अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों से हवा के जरिए आ सकते हैं और इनमें आमतौर पर कोई घातक उपकरण नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने स्थानीय सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं पाया गया।

पिछली घटनाओं और इस बार मिली जानकारी के आधार पर अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये गुब्बारे किसी बड़े साजिश या संदेश का हिस्सा हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम लगातार गांव और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। साथ ही, ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को बिना पुलिस को बताए न छुएं और तुरंत सूचना दें।

इस प्रकार की घटनाओं ने पूरे ऊना जिले में अलर्ट बढ़ा दिया है और राज्य के अन्य जिलों के प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि सतर्क रहना और हर घटना की गंभीरता से जांच करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। स्थानीय लोग भी अब ज्यादा चौकस हैं और प्रशासन की इस दिशा में उठाई गई कार्रवाई को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं।

## पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव संपन्न, 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे

**(जीएनएस)।** पंजाब में रविवार, 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया। राज्यभर में आयोजित इन चुनावों में वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराई गई। इस बार पंजाब के 23 जिलों में कुल 347 जिला परिषदों और 2,838 ब्लॉक समितियों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में कुल 9,775 उम्मीदवार चुनावों में भाग ले रहे थे। मतदान के बाद वोटों की गिनती 17 दिसंबर को होगी।

राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए। चुनाव के संचालन के लिए लगभग 90,000 कर्मचारी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद, राज्य में लगभग 48 प्रतिशत मतदान ही दर्ज किया गया। मतदान के दौरान संगरूर के मंगवाल गांव में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार हमें बहुत संघर्ष और बलिदानों के बाद मिला है और प्रत्येक मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट डालना चाहिए। सीएम मान ने विशेष

रूप से कहा कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित हैं, इसलिए उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो और समाधान के प्रयास करता हो। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने घरों से निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें।

चुनाव आयोग ने पहली बार 23 जिलों में वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरनतारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला और मोगा जिलों में आईपीएस अधिकारियों को भी पर्यवेक्षक बनाया गया ताकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो। खुफिया जानकारी और पुलिस रिपोर्टों के आधार पर, चुनाव आयोग ने 860 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील और 3,405 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया। इन सभी केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कुल 18,224 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए, जहां बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी के 340 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के तीन उम्मीदवार और आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्विरोध जीत गए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा रही है या नामांकन खारिज किए जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनाव राज्य के स्थानीय प्रशासन और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। अधिकारियों और चुनाव आयोग के सतर्क इंतजामों ने चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने में मदद की है। अब जनता की निगाहें 17 दिसंबर को आने वाले परिणामों पर हैं, जो आगामी स्थानीय राजनीति और क्षेत्रीय सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।